



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238866  
CG-DL-E-16092022-238866

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944

No. 216]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2022

मामला संख्या: एडी (एसएसआर) 04/2022

**विषय:** चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मोनोआइसोप्रोपाइल अमाइन” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

**फा.सं. 7/12/2022-डीजीटीआर.**—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष मै. अल्काइल अमाइन्स कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “मोनोआइसोप्रोपाइल अमाइन” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क, (5) के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए, तो उसे लागू करने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर वह निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित

है कि क्या शुल्क की समामि से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समामि से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरुआत अधिसूचना सं. 14/46/2016- डी जी ए डी दिनांक 15 फरवरी, 2017 द्वारा की गई थी। इसी मामले में, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में अधिसूचना सं. 14/46/2016-डीजीएडी दिनांक 12 फरवरी, 2018 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिन्हें अधिसूचना सं. 14/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मार्च, 2018 के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। यह शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया था और दिनांक 20 मार्च, 2023 को इसका समाप्त होना निर्धारित है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित था, जो निम्नानुसार है :

विचाराधीन उत्पाद “ मोनोआइसोप्रोपाइल अमाइन” है जिसे एमआईपीए के रूप में भी जाना जाता है। मोनोआइसोप्रोपाइल अमाइन एक कार्बनिक यौगिक, एक अमाइन है। यह एक बेस है जो अमाइन के लिए विशिष्ट है। यह अमोनिया जैसी गंध के साथ एक हाइड्रोस्कोपिक रंगहीन तह है। इसका गलनांक - 95.2 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 32.4 डिग्री सेल्सियस है। यह जल में घुलनशील है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और इसका फ्लैस प्वाइंट 37 डिग्री सेल्सियस है। एमआईपीए को एनहाइड्रस (99.5 प्रतिशत) में उत्पादित किया जाता है। इसके तरल रूप को एनहाइड्रक रूप में जल मिलाकर प्राप्त किया जाता है, जिसमें क्रेता की जरूरत के अनुसार वांछित स्तर तक इसके सांद्रण के स्तर को कम किया जाता है। इसे वाणिज्यिक रूप से अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर एनहाइड्रस रूप और जलीय रूप दोनों में बेचा जाता है।

5. चूंकि वर्तमान याचिका, निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है, इसलिए स्थापित न्याय शास्त्र और प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में यथापरिभाषित के अनुसार रहेगा।

#### ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे पर प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में भी जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

#### घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदक मै. अल्काइल अमाइन्स कैमिकल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबंधित हैं।

8. इसके महेनजर और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया है और यद्यपि, नियम 5(3) की अपेक्षाएं निर्णायक समीक्षा आवेदन पर लागू नहीं होती हैं, तथापि, यह नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

#### ड. संबद्ध देश

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

**च. पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना****सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजारचालित है, तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

11. आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। आवेदक ने इसके अलावा, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की पूरक सूचना दी है। यद्यपि, आवेदक ने यूएसए से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, तथापि आवेदक ने डी जी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है और याचिकाकर्ता द्वारा सूचित मात्रा की तुलना में यू एस से आयातों की मात्रा काफी कम पाई है। अतः प्राधिकारी, इस स्तर पर और जांच होने तक सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ यू एस ए से आयात कीमत को नहीं अपनाते हैं। जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों को जोड़कर सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने पर विचार किया है।

12. हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां करने और इस अधिसूचना में विहित समय सीमाओं के भीतर अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में विधिवत रूप से साक्ष्यांकित दावे करने की सलाह दी जाती है।

**निर्यात कीमत**

13. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की गणना के लिए डी जी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार आयात कीमत का विचार किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा कमीशन, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

14. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक है, जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटित कीमत पर निर्यात की जा रही है और इस प्रकार, पाटन जारी है और इस जांच की शुरुआत न्यायोचित है।

**छ. क्षति के जारी रहने और पुनरावृत्ति की संभावना**

15. भारतीय मांग में आयातों के पर्याप्त हिस्से, कीमत कटौती, कम लाभप्रदता, तीसरे देशों के पाटन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, अन्य देशों से क्षतिकारी निर्यात, चीन के उत्पादकों की पर्याप्त क्षमता, क्षमता विस्तार, आयातों का संभावित ह्रासकारी प्रभाव और वस्तु की समाप्ति पर भी घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के कारण पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

**ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

16. आवेदकों द्वारा किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार पाटन और क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

**ज. जांच की अवधि (पीओआई)**

17. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 महीने) तक है। क्षति जांच अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल है। जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण में जांच की जा सकती है।

**झ. प्रक्रिया**

18. वर्तमान समीक्षा में मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम सं. 14/46/2016-डीजीएडी दिनांक 12 फरवरी, 2018 के माध्यम से प्रकाशित यथासंशोधित समस्त पहलू शामिल हैं। नियमावली के नियम 6,7,8,9, 10, 11, 16, 17,18,19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**ट. सूचना प्रस्तुत करना**

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in को ई मेल के माध्यम से तथा adg13-dgtr@gov.in, और adv12-dgtr@gov.in. को एक प्रति के साथ भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, आयातकों और संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 17 में उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट अर्थात <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

**ठ. समय-सीमा**

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in , adg13-dgtr@gov.in, और adv12-dgtr@gov.in. को ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के अगोपनीय संस्करण प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ कर सकते हैं।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तौर तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

**ण. असहयोग**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2022

**(Case No. AD (SSR)-04/2022)**

**Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Monoisopropylamine originating in or exported from China PR.**

**F. No. 7/12/2022-DGTR.**—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s Alkyl Amines Chemicals Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for sunset review investigation of antidumping duty on imports of "Monoisopropylamine" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**A. Background of previous investigation**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide notification No. 14/46/2016-DGAD on 15th February 2017. In the same matter, the final finding was issued vide notification No. 14/46/2016 -DGAD dated 12th February 2018 confirming imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject countries, which were implemented vide Notification No. 14/2018-Cus (ADD), dated 21st March 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 20th March 2023.

**B. Product under consideration**

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows

*“The product under consideration is “Monoisopropylamine”, also known as MIPA. Monoisopropylamine is an organic compound, an amine. It is a base, as typical for amines. It is a hygroscopic colourless liquid with ammonia-like odor. Its melting point is –95.2 °C and its boiling point is 32.4 °C. It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at –37 °C. MIPA is produced in anhydrous (99.5%). Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which concentration level reduced to desired level as per buyer’s requirement. It is commercially sold both in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.”*

5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.

**C. Like Article**

6. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the

domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has been examined by the Authority in the previous investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**D. Domestic industry and standing**

7. The application has been filed by M/s Alkyl Amines Chemicals Limited. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. The applicant has further certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importers in India.
8. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application, and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

**E. Subject country**

9. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

**F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping**

**Normal value**

10. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The normal value has accordingly been determined in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
11. The applicant had proposed to determine normal value on the basis of export price from United States of America. The applicant further supplemented the normal value on the basis of price payable in India based on the cost of production in India and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Even though the applicant has claimed normal value on the basis of import price from USA, the Authority analysed data received from DG Systems and found much lower volume of imports from USA as compared to volume reported by the petitioner. Therefore, the Authority has, at this stage, and pending investigation, not adopted the import price from USA for the purpose of determination of normal value. The Authority has, for the purpose of this initiation, considered the constructed normal value for China PR on the basis of best estimates of cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits.
12. The interested parties are advised to offer their comments, and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value, having regard to the provisions of para-7 and 8 of Annexure-I within the time limits prescribed in this notification.

**Export price**

13. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for determination of export price. The Authority has, however considered import price as per DG Systems data for computation of export price. The export price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.



**Dumping margin**

14. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export price, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus, indicating continued dumping so as to justify initiation of this investigation.

**G. Likelihood of continuation or recurrence of injury**

15. There is prima facie evidence of continuation of dumping and consequent injury on account of significant share of imports in the Indian demand, price undercutting, low profitability, third countries dumping, price attractiveness of the Indian market, injurious exports to other countries, significant capacities with Chinese producers, capacity expansion, likely suppressing impact of imports and likely injury to the domestic industry in event of cessation of duties. The information provided by the applicant, prima facie, shows continuation of dumping of subject goods from the subject country, and likelihood of injury to domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

**H. Initiation of sunset review investigation**

16. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**I. Period of Investigation (POI)**

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation. The data beyond period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

**J. Procedure**

18. The present review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/46/2016-DGAD dated 12th February 2018 as amended. The provisions of Rules 6,7,8,9, 10, 11, 16, 17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**K. Submission of information**

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, and adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers, and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 17 above.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.



23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**L. Time Limit**

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in), [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**M. Submission of information on confidential basis**

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all the information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**N. Inspection of Public File**

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**O. Non-cooperation**

35. In case where an interested party refuses access to or otherwise, does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority